

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति

प्रलम्ब के लिये:

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति, **खुदरा मुद्रास्फीति**, भारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक नीति, सकल घरेलू उत्पाद, आपूर्ति शृंखला

मेन्स के लिये:

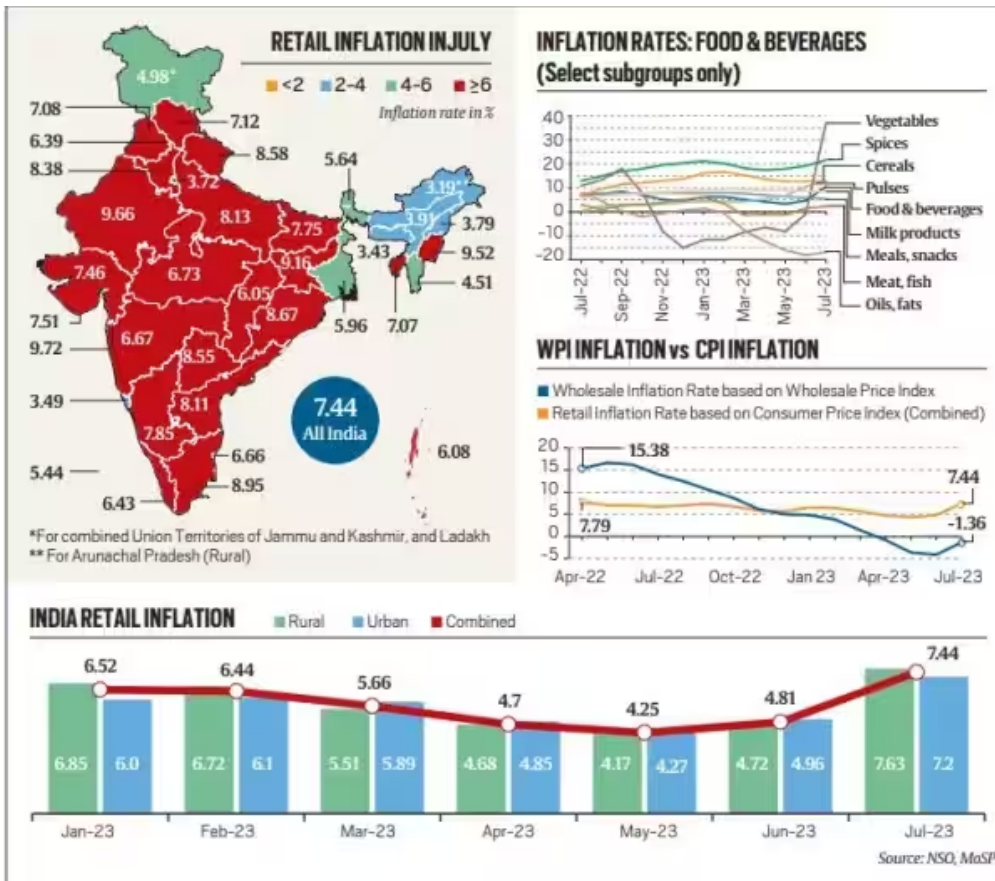
भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव

[स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

जुलाई 2023 में **खुदरा मुद्रास्फीति** में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो **7.44%** तक पहुँच गई, जिससे भारत के लिये गोलडीलॉक्स परदृश्य तैयार हुआ जो **नविशकों एवं बचतकर्ताओं की आर्थिक स्थिति** के बारे में अनश्चितताओं को दर्शाता है।

- गोलडीलॉक्स परदृश्य एक अर्थव्यवस्था के लिये आदर्श स्थिति का वर्णन करता है जहाँ अर्थव्यवस्था बहुत अधिक वसितार या संकुचन नहीं कर रही है। गोलडीलॉक्स अर्थव्यवस्था में स्थिर आर्थिक विकास होता है, जिससे मंदी को रोका जा सकता है, **लेकिन इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाए।**



भारत का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और अनुमान:

■ GDP अनुमान:

- वर्ष 2023-24 के लिये अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि 6.5% है, जबकि बैचमार्क सेंसेक्स सूचकांक वर्तमान में 65,000 अंक पर है।
- दूसरी ओर आगामी महीनों में सोने और बैंक जमा दरों के स्थिर रहने की उम्मीद है।

■ मुद्रास्फीति का अनुमान:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) का अनुमान है कि वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही तक मुद्रास्फीति 5% से ऊपर रहेगी और संभावित रूप से वर्तमान तिमाही (जुलाई-सितंबर) 2023 में 6.2% तक पहुँच जाएगी जो RBI के 4% के कम्फर्ट लेवल (Comfort Level) से अधिक होगी।

■ खाद्य मूल्य दबाव:

- अगले कुछ महीनों तक खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊँची रहने की आशंका है। जुलाई के आँकड़ों के अनुसार अनाज व दालों (दोनों में कुल 13%), मसालों (21.6%), दूध (8.3%) के साथ-साथ सब्जियों की कीमतों (37.3%) में वृद्धि देखी गई है।
- सरकारी हस्तक्षेप और नई फसल की आवक से अंततः इस दबाव के कम होने की उम्मीद है।

■ ब्याज दरें और मौद्रिक नीति:

- उच्च मुद्रास्फीति अनुमानों को देखते हुए ब्याज दर में किसी प्रकार की कटौती की संभावना अगले वित्तीय वर्ष (2024-25) तक के लिये टाल दी गई है।
- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) द्वारा आगामी बैठक में नीतित गत दरों को बनाए रखने की संभावना है जिसमें संभावित रूप से ब्याज दर में पहली कटौती अगले वित्तीय वर्ष में होगी।

■ बाज़ार दृष्टिकोण:

- महँगाई और ऊँची ब्याज दरों के बावजूद भारतीय बाज़ार ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
- दृढ़ आय की संभावनाओं और स्टैबल मैक्रो कंडीशन के समर्थन से भारत ने अन्य बाज़ारों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

बढ़ती महँगाई का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

■ बाज़ारों पर प्रभाव:

- जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो स्टॉक की कीमतें कम आँकी जाती हैं और सोने का मूल्य बढ़ जाता है। बढ़ती मुद्रास्फीति के कारणात्मक शक्ति कम हो जाती है जिससे वास्तविक आय कम हो जाती है।
- इसके अतिरिक्त उच्च मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप ब्याज दरें उच्च होती हैं, जिससे इक्विटी की लागत प्रभावित होती है।
 - अप्रैल 2022 से भारतीय रिज़र्व बैंक की रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के कारण उधार दरों में समग्र वृद्धि हुई है, जिससे विभिन्न प्रकार के ऋणों का काफी प्रभाव पड़ा है।

■ आय पुनर्वितरण:

- मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न समूहों पर असमान प्रभाव पड़ सकता है। देनदारों से प्राप्त धन का मूल्य घटने से लेनदारों को नुकसान हो सकता है।
- इसके विपरीत देनदारों को उन पैसों से ऋण चुकाने से लाभ हो सकता है जिनकी कीमत उनके उधार लेने के समय की कीमत से कम है।

■ अंतरराष्ट्रीय प्रतस्पर्द्धात्मकता:

- किसी देश में उच्च मुद्रास्फीति उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकती है। यदि घरेलू कीमतें व्यापारिक साझेदार देशों की तुलना में तेज़ी से बढ़ें तो देश का निर्यात वैश्विक बाज़ार में कम आकर्षक हो सकता है।

■ पारिश्रमिक-मूल्य चक्र:

- मुद्रास्फीति के कारण कभी-कभी बढ़ी हुई पारिश्रमिकी और मूल्य चक्र की शुरुआत हो सकती है। बढ़ती लागत के साथ समन्वय बनाने के लिये श्रमिक उच्च मज़दूरी की मांग करते हैं और व्यवसायों में लगने वाली उच्च लागतों के कारण कीमतें उच्च होती हैं जिनका दबाव उपभोक्तों पर पड़ता है। इस चक्र के परिणामतः मुद्रास्फीति की स्थिति लगातार बनी रह सकती है।

आगे की राह

- मुद्रास्फीति की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रास्फीति के दबाव को प्रबंधित करने के लिये मलिकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें खाद्य कीमतों को स्थिर करने, आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार करने और सुरक्षात्मक मौद्रिक नीति बनाए रखने जैसे लक्ष्य उपाय शामिल हो सकते हैं।
- सरकार को संतुलित बजट बनाए रखने, अनावश्यक व्यय को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले सुधारों एवं उपायों के माध्यम से राजस्व अर्जन को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिये।
- RBI को सतर्क और डेटा-संचालित मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाना जारी रखना चाहिये। इसमें आर्थिक विकास संबंधी प्रभाव पर विचार करते हुए मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिये ब्याज दरों को समायोजित करना शामिल हो सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????? :

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति उसमें वृद्धि निम्नलिखित कनि कारणों से होती है? (2021)

1. वसितारित नीतियाँ
2. राजकोषीय प्रोत्साहन
3. मुद्रास्फीति सूचकांकन मज़दूरी
4. उच्च क्रय शक्ति
5. बढ़ती ब्याज दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2, 3 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. खाद्य वस्तुओं का 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) भार (Weightage) उनके 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) में दिये गये भार से अधिक है।
2. WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान तथा प्रमुख नीतगित दरों के निर्धारण हेतु WPI को अपना लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/inflation-and-current-outlook-of-indian-economy>

